नई दिल्ली, शनिवार, 24 फरवरी 2018

दैनिक जागरण
नोएडा

बदलाव एनएमआरसी में केंद्र से चेयरमैन और प्रदेश से बनेगा एमडी

एक्वा लाइन मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन (एनएमआरसी) में अब राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी 50 फीसदी की भागीदारी हो गई है। जिसके चलते नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तेजी आने की उम्मीद है। इसके लिए करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अब एनएमआरसी के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। जिसमें पांच निदेशक केंद्र सरकार और पांच निदेशक प्रदेश सरकार के होंगे। इसके साथ ही एनएमआरसी में अब चेयरमैन केंद्र का होगा और प्रबंध निदेशक (एमडी) प्रदेश सरकार का होगा।

शुक्रवार को एनएमआरसी की 15वीं बोर्ड बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नोएडा प्राधिकरण के सीईओ और एनएमआरसी के प्रबंध निदेशक आलोक टंडन ने की। बैठक में कुल छह बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान बताया गया कि गत 19 फरवरी को सचिव शहरी एवं आवासन मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 19 फरवरी को अनुबंध हस्ताक्षर होकर प्राप्त हो गया है।

जिसके चलते अब एनएमआरसी में केंद्र सरकार की 50 फीसदी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो गई है। इसके साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 970 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जाएगी। जिसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत 5503 करोड़ की 14.18 धनराशि के बराबर 687.62 करोड़ रुपये अंशदान के रूप में मिलेंगे। अब एनएमआरसी को 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत यूपी सरकार की सहभागिता वाली ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

एनएमआरसी के बोर्ड में शामिल होंगे केंद्र और प्रदेश के पांच-पांच निदेशक

अब एनएमआरसी के बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। जिसमें भारत सरकार द्वारा पांच निदेशकों के नाम दिए जाएंगे। इनमें से एक निदेशक अध्यक्ष होगा। इसी तरह यूपी सरकार भी पांच निदेशक नामित करेगी। जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होंगे। इस दौरान बैठक में मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि प्रोजेक्ट के सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एवं सिग्नलिंग का कार्य 80 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है। ट्रैक पर टेस्ट ट्रायल भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही मार्च के पहले हफ्ते में यूपीपीटीसीएल द्वारा पर्याप्त बिजली मिलने पर ट्रैक पर ट्रायल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। वहीं एनएमआरसी की सिटी बस योजना की भी समीक्षा करते हुए सदस्यों ने राजस्व बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं।

एनएमआरसी में केंद्र सरकार की 50 फीसदी भागीदारी, नोएडा-ग्रेनो के लिए केंद्र से जल्द जारी होंगे 970 करोड़ रुपये

एनएमआरसी में 744 का होगा स्टॉफ, जारी किए जा रहे नियुक्ति पत्र

एनएमआरसी में 744 स्टाफ की भर्ती का परिणाम घोषित किया जा चुका है और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया के तहत 92 अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिनका परिक्षण डीएमआरसी के शास्त्री पार्क स्थित परिक्षण केंद्र में शुरू हो चुका है। बैठक में एनएमआरसी के प्रस्तावित बजट 2018-19 को भी मंजूरी दी गई है। बजट में कुल 2320 करोड़ रुपये की आय तथा व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिसमें आगामी वित्त वर्ष में भारत सरकार, यूपी सरकार तथा एनएमआरसी योजना बोर्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि व उनके सापेक्ष मेट्रो तथा सिटी बस परियोजना अनुमानित आय का विवरण प्रस्तुत किया गया।